



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1,
PART I—Section 1
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 258]

नई दिल्ली, शुक्रवार, सितम्बर 21, 2001/भाद्र 30, 1923

No. 258]

NEW DELHI, FRIDAY, SEPTEMBER 21, 2001/BHADRA 30, 1923

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

पाटनरोधी एवं सम्बद्ध शुल्क महानिदेशालय

जांच शुरूआत की अधिसूचना

नई दिल्ली, 21 सितम्बर, 2001

विषय :—यूएसए, जापान, सिंगापुर और यूरोपीय संघ के मूल के अथवा वहां से निर्यातित "आणविक भार 3000 से 4000 के फ्लैक्सिबल स्लैबस्टॉक पोलिओल" के भारत में आयातों के संबंध में पाटनरोधी जांच आरंभ करना।

सं. 41/1/2001-डीजीएडी.—मै. मनाली पेट्रोकेमिकल लि., चेन्नई ने 1995 में यथा संशोधित सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 तथा सीमाशुल्क टैरिफ (पाटित वस्तुओं की पहचान, उन पर पाटनरोधी शुल्क का आंकलन तथा संग्रहण और क्षति निर्धारण) नियम, 1995 के अनुसार निर्दिष्ट प्राधिकारी (जिसे एतदपश्चात प्राधिकारी कहा गया है) के समक्ष एक याचिका दायर की है, जिसमें यूएसए, जापान, सिंगापुर तथा यूरोपीय संघ (जिन्हें इसमें एतदपश्चात संबद्ध देश/क्षेत्र कहा गया है) से आणविक भार 3000 से 4000 के फ्लैक्सिबल स्लैबस्टॉक पोलिओल के पाटन का आरोप लगाया गया है और पाटनरोधी जांच आरंभ करने तथा पाटनरोधी शुल्क लगाने का अनुरोध किया है।

2. विचाराधीन उत्पाद :

वर्तमान याचिका में विचाराधीन उत्पाद आणविक भार 3000 से 4000 का फ्लैक्सिबल स्लैबस्टॉक पोलिओल (जिसे एतदपश्चात सम्बद्ध वस्तु कहा गया है) है।

याचिकाकर्ता ने दावा किया है कि आणविक भार 3000 से 4000 का फ्लैक्सिबल स्लैबस्टॉक पोलिओल अध्याय शीर्ष 3907.20 में वर्गीकृत है लेकिन इसकी निकासी सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 के अध्याय शीर्ष 3907.99 और 3907.91 के अंतर्गत भी की जा रही है। सीमाशुल्क वर्गीकरण केवल संकेतात्मक है और यह वर्तमान जांच के दायरे पर किसी भी प्रकार से बाध्यकारी नहीं है।

3. घरेलू उद्योग

यह याचिका मै0 मनाली पेट्रोकेमिकल्स लि0, चेन्नई द्वारा दायर की गई है। याचिकाकर्ता का दावा है कि वह भारत में सम्बद्ध वस्तु का एकमात्र उत्पादक है। इस प्रकार याचिकाकर्ता उपरोक्त नियमों के नियम 5(3)(क) के अनुसार घरेलू उद्योग की ओर से याचिका दायर करने की हैसियत संबंधी मानदण्ड को पूरा करता है।

4. शामिल देश:

वर्तमान जांच में शामिल देश यूएसए, जापान, सिंगापुर और यूरोपीय संघ हैं।

5. समान वस्तु:

याचिकाकर्ता का दावा है कि उसके द्वारा उत्पादित माल संबंधित देशों/क्षेत्रों के मूल के अथवा वहां से निर्यातित माल के समान वस्तु है। इसलिए, वर्तमान जांच के उद्देश्य के लिए याचिकाकर्ता द्वारा उत्पादित माल को उपरोक्त नियमों के अर्थों के भीतर संबद्ध देशों/क्षेत्र से आयातित वस्तु के समान वस्तु माना जा रहा है।

6. सामान्य मूल्य

चूंकि विचाराधीन उत्पाद खुले बाजार में सामान्य रूप से व्यापार नहीं की जाने वाली औद्योगिक कच्ची सामग्री है इसलिए घरेलू उद्योग संबद्ध देशों के घरेलू बाजार में संबद्ध वस्तुओं की कीमतों के बारे में सूचना प्रस्तुत करने में समर्थ नहीं रहा है। अतः धारा 9क(1)(ग)(i) के अनुसार याचिकाकर्ता द्वारा संबद्ध देशों के सम्बद्ध में सामान्य मूल्य का दावा परिकलित सामान्य मूल्य के आधार पर किया गया है। उन्होंने अनुरोध किया है कि सम्बद्ध देशों में परिकलित सामान्य मूल्य सम्बद्ध वस्तु के लिए सम्बद्ध देशों/क्षेत्र में सामान्य मूल्य का अच्छा सूचक है विशेषकर इसलिए चूंकि कीमतें कच्चे माल की अंतर्राष्ट्रीय कीमतों के आधार पर निर्धारित की जाती हैं और इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि प्रचालन अथवा प्रौद्योगिकी के स्तर में कोई महत्वपूर्ण अन्तर नहीं है।

प्राधिकारी ने घरेलू उद्योग के तर्क को स्वीकार कर लिया है और शुरुआती जांच के प्रयोजनार्थ उसे सामान्य मूल्य के लिए प्रथम दृष्टया साक्ष्य के रूप में मान लिया है।

7. निर्यात कीमत:

याचिकाकर्ता ने सम्बद्ध देशों/क्षेत्र से हुए निर्यातों की कीमत का दावा आंकड़ों के गौण स्रोतों, अर्थात् मै0 इंटरनेशनल बिजनैस, इन्फोरेमेशन सर्विस, मुम्बई, जिनके आंकड़े सीमाशुल्क दैनिक सूची पर आधारित हैं, के आधार पर किया है। गौण स्रोत के आंकड़ों से याचिकाकर्ता ने विवरण के आधार पर आंकड़े अलग किए हैं और विचाराधीन उत्पाद के सौदों को एक साथ मिला दिया है। कारखानागत स्तर पर निर्यात कीमत निकालने के लिए समुद्री भाड़े, समुद्री बीमे के कारण समायोजनों का दावा किया गया है।

8. पाटन मार्जिन

इस बात के प्रथम दृष्टया साक्ष्य हैं कि सम्बद्ध देशों/क्षेत्रों में सम्बद्ध वस्तु का सामान्य मूल्य कारखानागत निर्यात कीमत से पर्याप्त रूप से अधिक है जो प्रथम दृष्टया संकेत करता है कि सम्बद्ध वस्तु सम्बद्ध देश/क्षेत्र के निर्यातकों द्वारा पाटित की जा रही है।

9. क्षति एवं कारणात्मक संबंध

क्षति से संबंधित विभिन्न संकेतक जैसे सम्बद्ध देशों/क्षेत्र से हुए आयातों के बाजार हिस्से में वृद्धि, उत्पादन और क्षमता उपयोग में गिरावट, बिक्री मात्रा और मूल्य में गिरावट, लाभप्रदता में गिरावट, कीमत कटौती, सम्बद्ध वस्तु की सामान सूची में वृद्धि समग्र एवं संयुची रूप से प्रथम दृष्टया यह बताते हैं कि घरेलू उद्योग को पाटन के कारण वास्तविक क्षति हुई है।

10. पाटनरोधी जांच की शुरुआत

उपरोक्त पैराग्राफों को देखते हुए निर्दिष्ट प्राधिकारी सम्बद्ध देशों/क्षेत्र के मूल की अथवा वहां से निर्यातित सम्बद्ध वस्तु का कथित पाटन होने, उसकी मात्रा तथा उसके प्रभाव की पाटनरोधी जांच आरंभ करते हैं।

11. जांच की अवधि :

वर्तमान जांच के प्रयोजन के लिए जांच की अवधि 1-10-2000 से 30-6-2001 तक की है।

12. सूचना देना:

सम्बद्ध देश के निर्यातकों और भारत के आयातकों, जिनके इस से जांच संबंधित होने की जानकारी है, को अलग से लिखा जा रहा है कि वे अपने विचार तथा संबंधित सूचना निर्धारित प्रपत्र में तथा निर्धारित ढंग से निर्दिष्ट प्राधिकारी, पाटनरोधी एवं सम्बद्ध शुल्क महानिदेशालय, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, वाणिज्य विभाग, भारत सरकार, उद्योग भवन, नई दिल्ली-110011 को भेज दें।

उपरोक्त नियम के नियम 6(5) के अनुसार निर्दिष्ट प्राधिकारी जांचाधीन वस्तु के औद्योगिक उपयोक्ताओं को भी अवसर प्रदान कर रहे हैं, जो ऐसी सूचना प्रस्तुत कर सकते हैं जो पाटन, क्षति और कारणात्मक संबंधों के बारे में जांच से संबंधित है। कोई अन्य हितबद्ध पार्टी भी नीचे दी गई समयावधि के भीतर जांच से संबंधित अनुरोध दे सकती है।

13. समय-सीमा:

वर्तमान जांच से संबंधित कोई भी सूचना लिखित रूप में दी जाए जो उपरोक्त पते पर निर्दिष्ट प्राधिकारी के पास इस अधिसूचना के प्रकाशित होने की तारीख से 40 दिनों के भीतर पहुंच जानी चाहिए। लेकिन जिन ज्ञात निर्यातकों तथा आयातकों को अलग से लिखा जा रहा है, उन्हें अलग से लिखे गए पत्र की तारीख से 40 दिन के भीतर सूचना प्रस्तुत करनी होगी।

14. सार्वजनिक फाइल का निरीक्षण:

नियम 6(7) के अनुसार, कोई भी हितबद्ध पार्टी उस सार्वजनिक फाइल का निरीक्षण कर सकती है जिसमें अन्य हितबद्ध पार्टियों द्वारा प्रस्तुत किए गए साक्ष्यों के अगोपनीय अंश रखे गए हैं।

यदि कोई हितबद्ध पार्टी आवश्यक सूचना जुटाने से मना करती है या उचित समयावधि के भीतर उसे अन्यथा उपलब्ध नहीं कराती है अथवा जांच में अत्यधिक बाधा डालती है तो प्राधिकारी अपने पास उपलब्ध तथ्यों के आधार पर निष्कर्ष दर्ज कर सकता है तथा केन्द्रीय सरकार को यथोचित सिफारिशें कर सकते हैं।

एल. वी. सप्तप्रहृषि, निर्दिष्ट प्राधिकारी

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(Department of Commerce)

DIRECTORATE GENERAL OF ANTI-DUMPING AND ALLIED DUTIES

INITIATION NOTIFICATION

New Delhi, the 21st September, 2001

Sub:—Initiation of Anti-dumping investigation concerning imports of “Flexible Slabstock Polyol of molecular weight 3000 to 4000” into India originating in or exported from USA, Japan, Singapore and European Union.

No. 41/1/2001-DGAD.— M/s Manali Petrochemical Ltd., Chennai has filed a petition in accordance with the Customs Tariff Act, 1975 as amended in 1995 and Customs Tariff (Identification, Assessment and Collection of Anti Dumping Duty on Dumped Articles and for Determination of Injury) Rules, 1995 before the Designated Authority (hereinafter referred to as the Authority) alleging dumping of Flexible Slabstock Polyol of molecular weight 3000 to 4000 originating in or exported from USA, Japan, Singapore and European Union (hereinafter referred to as subject countries/territory) and requested for initiation of Anti Dumping investigations and levy of anti dumping duties.

2. PRODUCT UNDER CONSIDERATION:

The product under consideration in the present petition is Flexible Slabstock Polyol of molecular weight 3000 to 4000 (hereinafter referred to as subject goods).

Petitioner has claimed that Flexible Slabstock Polyol of molecular weight 3000 to 4000 is classified in chapter heading 3907.20 but are also cleared under Chapter Headings 3907.99 and 3907.91 of the Customs Tariff Act, 1975. Customs classifications are indicative only and are in no way binding on the scope of the present investigation.

3. **DOMESTIC INDUSTRY**

The petition has been filed by M/s Manali Petrochemical Ltd., Chennai. The petitioner is the sole producer of the subject goods in India. Thus the petitioner satisfies the criteria of standing to file the petition on behalf of the Domestic Industry in terms of Rule 5(3) (a) of the Rules supra.

4. **COUNTRIES INVOLVED:**

The countries/territory involved in the present investigation are USA, Japan, Singapore and European Union.

5. **LIKE ARTICLE:**

The petitioner has claimed that the goods produced by them are like articles to the goods originating in or exported from subject countries/territory. Therefore, for the purpose of the present investigation, the goods produced by the petitioner is being treated as 'like articles' of the product imported from the subject countries/territory within the meaning of the Rules supra.

6. **NORMAL VALUE:**

According to Section 9 A(1) (c) (i) Normal Value in respect of subject country(ies) has been claimed by the petitioner based on Constructed Normal Value. The petitioner has mentioned that they tried to get information on prices of the subject goods in the domestic market of the subject countries. The petitioner has also made efforts to get price lists of the exporters or price evidence for their exports to third countries. The petitioner submits that they have not been able to get any evidence, with regard to the prices of the subject goods in the subject countries/territory or price list of the exporters either for sales in that country or for exports to other countries. The problem gets further accentuated due to the fact that the subject goods are not traded in the open market and such commercially sensitive information is not available to outsiders much less to the Indian Domestic Industry. They have further submitted that the Constructed Normal Value in the subject countries is a good indicator of the Normal Value in the subject countries/territory for the subject goods, particularly as the prices are determined on the basis of international prices of raw materials, and in view of the fact that there are no significant differences in the levels of operations or technology.

The Authority has accepted the argument of the Domestic Industry and considered the same as prima facie evidence for Normal Value for the purpose of initiation.

7. **EXPORT PRICE:**

The petitioner has claimed the export price from the subject countries/territory based on the secondary data sources, i.e M/s International Business Information Service,

Mumbai whose data is based on the Customs Daily List. From the data of secondary source, the petitioner has sorted the data on the basis of description and clubbed the transactions for the product under consideration. Adjustments have been claimed on account of ocean freight, marine insurance to arrive at the Export Price at ex-factory level.

8. **DUMPING MARGIN**

There is prima facie evidence that Normal Value of the subject goods in the subject countries/territory is significantly higher than the ex-factory export price indicating prima facie that the subject goods are being dumped by exporters from the subject countries/territory.

9. **INJURY AND CAUSAL LINK**

Various parameters relating to injury such as increase in market share of imports from subject countries/territory, decline in production and capacity utilisation, decline in the sales volume and value, decline in profitability, price suppression, increase in inventories of the subject goods, prima facie indicate collectively and cumulatively that the Domestic Industry has suffered material injury on account of dumping.

10. **INITIATION OF ANTI DUMPING INVESTIGATIONS**

The Designated Authority, in view of the foregoing paragraphs, initiates anti-dumping investigations into the existence, degree and effect of alleged dumping of the subject goods originating in or exported from the subject countries/territory.

11. **PERIOD OF INVESTIGATION**

The Period of Investigation for the purpose of the present investigation is 1.10.2000 to 30.6.2001.

12. **SUBMISSION OF INFORMATION**

The exporters in the subject countries and the importers in India known to be concerned with this investigation are being addressed separately to submit relevant information in the form and manner prescribed and to make their views known to the Designated Authority, Directorate General of Anti Dumping & Allied Duties, Ministry of Commerce & Industry, Department of Commerce, Government of India, Udyog Bhavan, New Delhi – 11 00 11.

As per Rule 6(5) of Rule supra, the Designated Authority is also providing opportunity to the industrial users of the article under investigation who can furnish information which is relevant to the investigation regarding dumping, injury and causality. Any other interested party may also make its submissions relevant to the investigation within the time limit set out below.

13. **TIME LIMIT**

Any information relating to the present investigation should be sent in writing so as to reach the Authority at the address mentioned above not later than forty days from the date of publication of this notification. The known exporters and importers, who are being addressed separately are however required to submit the information within forty days from the date of the letter addressed to them separately.

14. **INSPECTION OF PUBLIC FILE**

In terms of Rule 6(7), any interested party may inspect the public file containing non-confidential version of the evidence submitted by other interested parties. In case where an interest party refuses access to, or otherwise does not provide necessary information within a reasonable period, or significantly impedes the investigation, the Authority may record its findings on the basis of the facts available to it and make such recommendations to the Central Government as deemed fit.

L. V. SAPTHARISHI, Designated Authority